

02 अक्टूबर, 2024
आर्थिक, कृषि पात्र, अलावस्या
संवत् 2081
पृष्ठ : 12, मूल्य : ₹3.00

रांगी

बुधवार, ग्रा 09, अंक 342

* ओडिशा संस्करण

www.epaper.azadsipahi.in

आजाद सिपाही

कलम कलम बढ़ाये जा

महालया
आज



सत्यमेव जयते



आजादी का बिगुल फूंकने वाले अमर शहीदों के झारखण्ड में

श्री नरेन्द्र मोदी

माननीय प्रधानमंत्री

जी का हार्दिक अभिनंदन और जोहार

2 अक्टूबर, 2024



श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री



श्री हेमंत सोरेन
माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड



श्री संतोष कुमार गंगवार
माननीय सार्वजनिक सेवा मंत्री, झारखण्ड

रांची

त्रिपुरा, ग्र 09, अंक 342

आजाद सिपाही



प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए हजारीबाग तैयार मोदी आयेंगे, सौगात लायेंगे

- 79,150 करोड़ रुपये से अधिक के कुल परिव्यय के साथ धर्ती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभांग करेंगे।
- भाजपा की परिवर्तन यात्रा के समाप्ति समारोह में भी शामिल होंगे।



सुरक्षा में तीन हजार से अधिक जवान रहेंगे तैनात

आजाद सिपाही संवाददाता हजारीबाग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को झारखण्ड का दौरा करेंगे। वह दोपहर करीब तो बजे हजारीबाग में 83,300 करोड़ रुपये से अधिक परिव्यय की परिवर्तन यात्रा के समाप्ति करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर रांची एयरपोर्ट से लेकर झारीबाग तक सुरक्षा के पुकार इंतजाम रहेंगे। साथ ही सात एसपी, 45 डीएसपी, 100 इंस्पेक्टर और 400 सब इंस्पेक्टर भी तैनात किये जायेंगे। इनके अलावा ऐप की दो कंपनी की भी लगाया गया है। पीएम के कार्यक्रम स्थल पर आने

से पहले उनका कार्कोड हजारीबाग पहुंच गया है। मंत्रीवार को उनके कार्कोड ने यूनिवर्सिटी से गार्डी मैदान आने जाना का माँड़ छिल किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस और प्रशासन के लोग सड़क किनारे खड़े रहे। कार्कोड में एंबुलेंस के साथ एक दर्जन गाड़ियां शामिल थीं। जनजातीय के अनुसार जिला प्रशासन से रांची से एक सुरक्षी कंपनी का स्पेशल वाहन मंजूरा है। सुरक्षा की माने तो पीएम इसी गाड़ी से दौरानी गांधी मैदान सभास्थल का चक्रवाल लगा लाएंगे कि दो कंपनी की भी लगाया गया है। यह वाहन पांच सीट की है।

परिव्यय के साथ धर्ती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभांग करेंगे। वह अभियान का स्तर पर अंतिम रूप दिया जा रहा है।

झारखण्ड समेत 30 राज्यों को तोहफा: प्रधानमंत्री 79,150 करोड़ रुपये से अधिक के कुल

तिरुपति लड़ विवाद: एसआइटी जांच रोकी गयी

तिरुपति (आजाद सिपाही)। आंध्र प्रदेश के श्री वेंकेश्वर स्वामी मंदिर (तिरुपति मंदिर) के प्रसादम (लड्डूओं) में जानवरों की चर्चा मामले की एसआइटी जांच रोक दी गयी है। राज्य के डीजीपी द्वारा तिरुपति में कोटे में करोड़ 8,46,640

यूपी में 39,000 कर्मचारियों का वेतन रोका गया

लखनऊ (आजाद सिपाही)। उत्तरप्रदेश सरकार के 39,000 कर्मचारियों को इस महीने वेतन नहीं दिया जायेगा। वर्तोंकि इन कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का व्यापार पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया। गैरतलब है कि उत्तर प्रदेश में कुल 8,46,640

राज्यकर्मी हैं। प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को संपत्ति का व्यापार मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करने का आदेश दिया था। इसके लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया था। इनमें से 7,88,506 कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का व्यापार पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है। गैरतलब है कि उत्तर प्रदेश में कुल 8,46,640

नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले सीएम ने रखी मांग प्रधानमंत्री झारखण्ड आ रहे, हमारा हक 1.36 लाख करोड़ लौटायें: हेमंत

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। एक दिन पहले झामुमो ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला पत्र लिखा था।

आजाद सिपाही संवाददाता रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केंद्र से बकाया राशि देने की मांग लगातार कर रहे हैं। वह हम मंच से केंद्र पर 1.36 लाख करोड़ रुपये बकाया होने की बात रख रहे हैं और केंद्र से देने की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुखार को हजारीबाग अगमन से पहले एक बार फिर हेमंत ने इसे लेकर निशाना साधा है। इस बार झामुमो ने 1.36 लाख करोड़



रुपये बकाया को लेकर 'प्रधानमंत्री के नाम खुला पत्र' लिखा। इसमें लिखा था कि 1.26 लाख करोड़ रुपये का मिलेगा? पत्र में कोल्काता कंपनियों पर बकाया रकम के दावे का ब्रेकअप भी दिया है। इसके पहले झामुमो ने 1.36 लाख करोड़

झारखण्ड के लोगों का अधिकार है

हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वे पैसा केंद्रीय कोलं कंपनियों के अधिकार में हैं। ये राशि नहीं प्राप्त होने पर झारखण्ड की तरकी में क्षतिकर हो रही है। ये अधिकार पूरे झारखण्ड के लोगों का है।

10.30 बजे मुख्यमंत्री ने इसे शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर फिर पोस्ट किया।

असम के मुख्यमंत्री ने हेमंत सरकार पर फिर साधा निशाना झामुमो और कांग्रेस सरकार नहीं बना पायेगी: हिमंत

कहा, 3 अक्टूबर को जारी होगा भाजपा का बुनावी धोषणा पत्र भाजपा की परिवर्तन यात्रा को बताया सफल



आजाद सिपाही संवाददाता रांची। असम के मुख्यमंत्री और झारखण्ड के चुनाव सह-प्रभारी हिमंत सोरेन विश्वा सरमा के चुनाव सह-प्रभारी को जामुमो और कांग्रेस को बताया सफल है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनजातीय अदिवासी न्याय महाअभियान के तहत 1360 करोड़ रुपये से अधिक की लगत के 25 एकलव्य मॉडल को 25 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन करेंगे और 2,800 करोड़ रुपये से अधिक लगत के 25 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की आवासीय विद्यालयों की आवासीय लगायेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनजातीय अदिवासी न्याय महाअभियान के तहत 1360 करोड़ रुपये से अधिक की लगत का वाली कई परिवर्तन यात्रा और शिलान्यास करेंगे।

की कुर्सी पर आप बैठे हैं, और पूछे हमसे हैं कि आपने सुबे की जनता को बता दे सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम अपना चुनावी धोषणा पत्र 3 अक्टूबर को जारी करेंगे। हेमंत सोरेन पर साधा निशाना: सरमा ने कहा कि यह जन कर हैरानी होती है कि आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होने के बावजूद दूसरों से मांग रहे हैं। यानी की आप यह बात खुद ही स्वीकार कर चुके हैं कि आप में लोगों को देने की क्षमता नहीं है। आप में यह क्षमता नहीं है कि प्रदेश के लोगों का विकास कर सकें। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बावजूद आपने भाजपा का साहब, सत्ता में आप हैं, मुख्यमंत्री हैं, ना की हम, तो देने की

परिवर्तन यात्रा की समाप्ति में पौएम मोदी रहेंगे गोजूद

असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा का गोजूद में परिवर्तन यात्रा निकली है। पार्टी के विरोधी जांचों ने इसमें शिरकत की। भाजपा को जनता का अपार समर्थन नहीं है। उन्होंने कहा कि अक्टूबर के परिवर्तन यात्रा की समाप्ति होती है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मोजूद रहेंगे। हम अपना चुनावी धोषणा पत्र 3 अक्टूबर को जारी करेंगे।

(बीजेपी) दिया गया ? , तो इसमें साफ जाहिर होता है कि आप लोगों में प्रदेश के लोगों के लिए कुछ भी करने की इच्छा नहीं है। आप सिर्फ शासन करने की औपचारिकताएं ही निपार रहे हैं।



धरती आबा भगवान विरसा मुंडा

भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी जी
का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन

**न कहेंगे, न कहेंगे,
बदल के देंगे**

#HarshJmera #Modi #BJP #VandeModi



हर्ष अजमेरा

सदर विधानसभा (हजारीबाग)

संपादकीय

इच्छा मृत्यु पर गाइडलाइन

के द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से इच्छा मृत्यु को लेकर जारी किए गए गाइडलाइंस के मसौदे ने इस पर जारी बहस को तेज कर दिया है। इंडियन मैडिकल असोसिएशन ने भी यह कहते हुए अपनी की ओर लाइफ सोर्पोर सिस्टम हटाये जाने का फैसला करने की जिम्मेदारी डॉक्टरों पर डालना ठीक नहीं है। इससे उन पर दबाव बढ़ जायेगा। इच्छा मृत्यु के बाबनामक, कानूनी और चिकित्सकीय पहलू इससे जुड़े किसी भी मामले में फैसला लेना कठिन बना देते हैं। लेकिन पिर भी फैसला तो करना ही होता है। सुप्रीम कोर्ट भी 2018 में निश्चिय इच्छा मृत्यु की कुछ शर्तों के साथ इच्छा दे दिया है। ऐसे में फैसले की प्रक्रिया जितनी स्पष्ट और परिभाषित होगी, फैसला लेना और उसे लागू करना उतना आसान होगा। सरकार की ओर से गाइडलाइंस जारी करने की ओर वाले प्राइमरी मैडिकल बोर्ड में प्राइमरी फिजिशन के अलावा कम से कम दो ऐसे एक्सपर्ट होंगे, जिनमें पास कम

से कम 5 साल का अनुभव होगा। इसके बाद सेकंडरी मैडिकल बोर्ड इस फैसले की समीक्षा करेगा, जिसमें सीमोंपरा द्वारा मनोनीत एक रजिस्टर्ड मैडिकल प्रैक्टिशनर के अलावा दो एक्सपर्ट होंगे।

इसके साथ ही पेशेंट के परिवार की सहभागी भी जरूरी होगी। केस की बारीकी के आधार पर निकर्ष तो आज भी डॉक्टरों का होता है, लेकिन वे पेशेंट या परिजनों को पूरी स्थिति समझते हैं और पिर पेशेंट या परिवार फैसला करते हैं। फैसला करने से डॉक्टरों की हिचक समझी जा सकती है। दरअसल, वह प्रफेशन ही मरीजों को बचाने का है। डॉक्टर अखिरी पल तक मरीज को बचाने का प्रयास करते हैं, भले ही कुछ ममलों में यह कोरिश कानक हो जाता है। ऐसे में इलाज के दौरान किसी स्थायी बिंदु पर उन प्रयासों से हाथ खींचने का फैसला स्वाभाविक ही कई डॉक्टरों को अपने जैसे से अन्यथा लग सकता है। मगर यहाँ कई पहलू हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा दे दिया है कि जीवन की गणिया के साथ ही मौत की गणिया का सबल भी जुड़ा है। पिर संसाधनों के सर्वबृंद इस्तेमाल की भी बात है। अमर किसी मरीज के ठीक होने की संभावना नहीं रह गयी है, तो उन मैडिकल संसाधनों का उपयोग ऐसे मरीज को बचाने में करना चेताता है, ताकि वहाँ जारी रहे। इसके अनुसार, उन्हें बिना किसी घेदधार अलग से कार्ड जारी किये जायेंगे, भले ही उनकी सामाजिक

20 अक्टूबर तक सुझाव मांगे हैं।

उम्मीद की जाये कि आने वाले तमाम सुझावों की देशी ने बनी गाइडलाइन ज्यादा उपयुक्त और ज्यादा व्यावहारिक होगी।

की बारीकी के आधार पर निकर्ष तो आज भी डॉक्टरों का होता है, लेकिन वे पेशेंट या परिजनों को पूरी स्थिति समझते हैं और पिर पेशेंट या परिवार फैसला करते हैं। फैसला करने से डॉक्टरों की हिचक समझी जा सकती है। दरअसल, वह प्रफेशन ही मरीजों को बचाने का है। डॉक्टर अखिरी पल तक मरीज को बचाने का प्रयास करते हैं, भले ही कुछ ममलों में यह कोरिश कानक हो जाता है। ऐसे में इलाज के दौरान किसी स्थायी बिंदु पर उन प्रयासों से हाथ खींचने का फैसला स्वाभाविक ही कई डॉक्टरों को अपने जैसे से अन्यथा लग सकता है। मगर यहाँ कई पहलू हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा दे दिया है कि जीवन की गणिया के साथ ही मौत की गणिया का सबल भी जुड़ा है। पिर संसाधनों के सर्वबृंद इस्तेमाल की भी बात है। अमर किसी मरीज के ठीक होने की संभावना नहीं रह गयी है, तो उन मैडिकल संसाधनों का उपयोग ऐसे मरीज को बचाने में करना चेताता है, ताकि वहाँ जारी रहे। इसके अनुसार, उन्हें बिना किसी घेदधार अलग से कार्ड जारी किये जायेंगे, भले ही उनकी सामाजिक

महंगाई के दौर में संसाधनों की कमी के चलते अतिरिक्त खर्च उठा पानी सभी के लिए संभव नहीं।

परिवार पर देश के सभी बुजुर्गों को मुफ्त इलाज मुहूर्या करवाने का वायदा किया गया था। आयुष्मान भारत योजना की परिधि को विस्तार देते हुए, 70 वर्ष अधिवा इसमें अधिक आयु वर्ग के सभी चरिष्ट नागरिकों को इसमें शामिल करने के लिए योग्य हो गया है।

वास्तव में वह विचार लोकसभा

चुनाव 2024 के दौरान भाजपा द्वारा जारी संकल्प पत्र का ही अंश है,

जिसके तहत सरकार बनने

पर देश के सभी बुजुर्गों

को मुफ्त इलाज मुहूर्या

करवाने का वायदा किया गया था।

आयुष्मान भारत योजना की परिधि को विस्तार देते हुए, 70 वर्ष अधिवा

योजना के अंतर्गत, देश के लगभग 4.5

करोड़ परिवारों के

करीब 6 करोड़ वरिष्टजनों

को 5 लाख रुपये के निःशुल्क

स्वास्थ्य बीमा करवा से लाभान्वित

करने की बात कही जा रही है।

इसके अनुसार, उन्हें बिना किसी घेदधार अलग से कार्ड जारी किये जायेंगे, भले ही उनकी सामाजिक

महंगाई के निःशुल्क

स्वास्थ्य बीमा करवा से लाभान्वित

करने की बात कही जा रही है।

इसके अनुसार, उन्हें बिना किसी घेदधार अलग से कार्ड जारी किये जायेंगे, भले ही उनकी सामाजिक

महंगाई के निःशुल्क

स्वास्थ्य बीमा करवा से लाभान्वित

करने की बात कही जा रही है।

इसके अनुसार, उन्हें बिना किसी घेदधार अलग से कार्ड जारी किये जायेंगे, भले ही उनकी सामाजिक

महंगाई के निःशुल्क

स्वास्थ्य बीमा करवा से लाभान्वित

करने की बात कही जा रही है।

इसके अनुसार, उन्हें बिना किसी घेदधार अलग से कार्ड जारी किये जायेंगे, भले ही उनकी सामाजिक

महंगाई के निःशुल्क

स्वास्थ्य बीमा करवा से लाभान्वित

करने की बात कही जा रही है।

इसके अनुसार, उन्हें बिना किसी घेदधार अलग से कार्ड जारी किये जायेंगे, भले ही उनकी सामाजिक

महंगाई के निःशुल्क

स्वास्थ्य बीमा करवा से लाभान्वित

करने की बात कही जा रही है।

इसके अनुसार, उन्हें बिना किसी घेदधार अलग से कार्ड जारी किये जायेंगे, भले ही उनकी सामाजिक

महंगाई के निःशुल्क

स्वास्थ्य बीमा करवा से लाभान्वित

करने की बात कही जा रही है।

इसके अनुसार, उन्हें बिना किसी घेदधार अलग से कार्ड जारी किये जायेंगे, भले ही उनकी सामाजिक

महंगाई के निःशुल्क

स्वास्थ्य बीमा करवा से लाभान्वित

करने की बात कही जा रही है।

इसके अनुसार, उन्हें बिना किसी घेदधार अलग से कार्ड जारी किये जायेंगे, भले ही उनकी सामाजिक

महंगाई के निःशुल्क

स्वास्थ्य बीमा करवा से लाभान्वित

करने की बात कही जा रही है।

इसके अनुसार, उन्हें बिना किसी घेदधार अलग से कार्ड जारी किये जायेंगे, भले ही उनकी सामाजिक

महंगाई के निःशुल्क

स्वास्थ्य बीमा करवा से लाभान्वित

करने की बात कही जा रही है।

इसके अनुसार, उन्हें बिना किसी घेदधार अलग से कार्ड जारी किये जायेंगे, भले ही उनकी सामाजिक

महंगाई के निःशुल्क

स्वास्थ्य बीमा करवा से लाभान्वित

करने की बात कही जा रही है।

इसके अनुसार, उन्हें बिना किसी घेदधार अलग से कार्ड जारी किये जायेंगे, भले ही उनकी सामाजिक

महंगाई के निःशुल्क

स्वास्थ्य बीमा करवा से लाभान्वित

करने की बात कही जा रही है।

इसके अनुसार, उन्हें बिना किसी घेदधार अलग से कार्ड जारी किये जायेंगे, भले ही उनकी सामाजिक

महंगाई के निःशुल्क

स्वास्थ्य बीमा करवा से लाभान्वित

करने की बात कही जा रही है।

इसक

